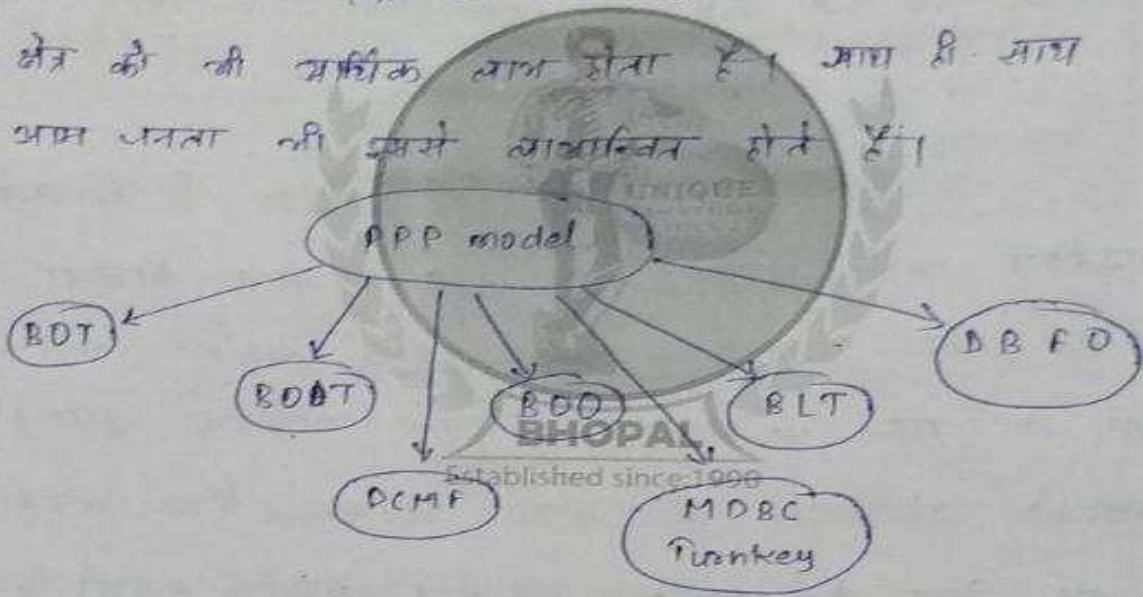


Q:- शार्वजत्रिक वीजी जागीदारी (PPP) क्या है? PPP के क्षेत्र में भारत की चुनौतियाँ क्या हैं? PPP के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है?

→ शार्वजत्रिक वीजी जागीदारी

PPP एक प्रकार का अनुबंध है जिसे सरकार एवं वीजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। इसमें सरकार को पूंजी निवेश, तकनीक एवं सूत प्रबंधन वीजी क्षेत्र में मिल जाता है वहीं वीजी क्षेत्र को की शारीक लाभ होता है। साथ ही साथ अपन अपना भी अपने लायान्वित होते हैं।



इस प्रकार PPP मॉडल को कई जागों में बांटा गया है जिसमें सामान्यतः वीजी उद्यमी किसी कार्य को पूरा करते हैं इसमें अपना लगान व्युत्पन्न करते हैं एवं फिर सरकार या एजेंसी को सौंप देते हैं।

PPP की चुनौतियाँ

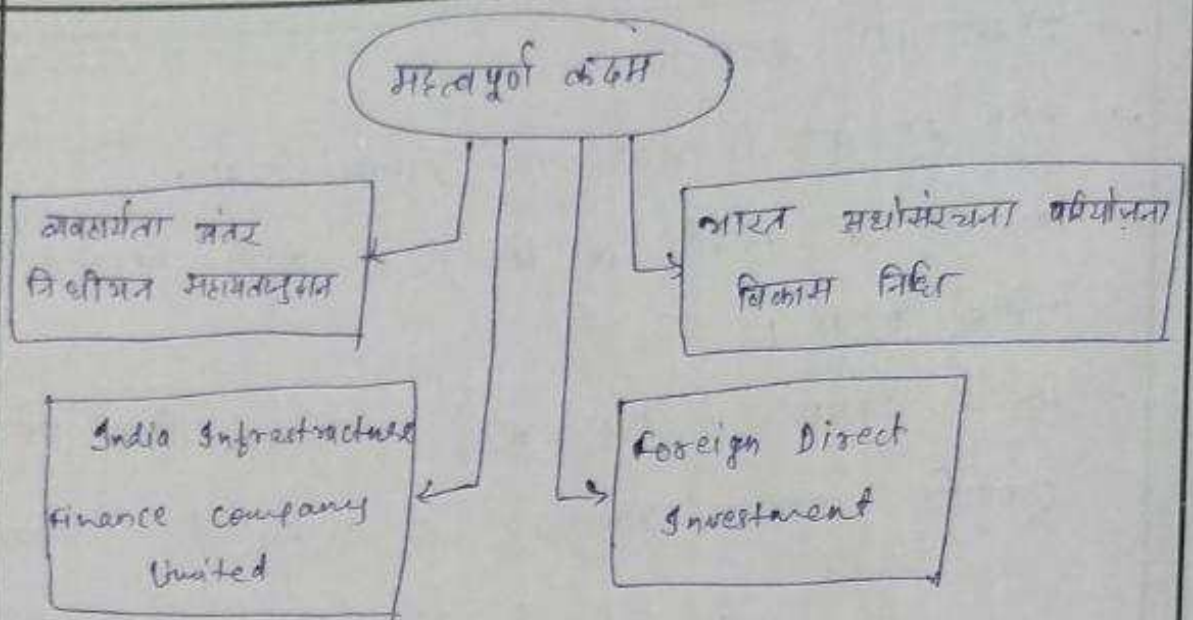
PPP मॉडल में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनमें -
 → भारत जैसे विकासशील देश की वीजी प्रक्रिया

- प्रौद्योगिकी का अडिगत्व रहेगा ।
- PPP का कूट ही क्षेत्रों तक सीमित रहना ।
- सरकारों के बदलने की स्थिति में इसमें विपरित प्रभाव पड़ना ।
- किसी विवाद के हल करने के लिए तीव्र एवं द्रुतगामी न्यायालय / प्राधिकरण का न होना ।

इन सभी कारणों से PPP मॉडल में उद्यमी निवेश करने से बचते हैं। कई जगह तो उद्यमी निवेश करने में कोई जिज्ञासा ही नहीं दिखाते। वहीं कई जगहों पर उद्यमी रुक विमर्श कर उसका संचालन करते हैं। PPP मुख्यतः केन्द्रों होता है जिससे पिछड़े कुछ जगहों को उन्नति मिलने में विवकल होती है। उदाहरणतः महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आदि जैसे बड़े शहरों में उद्यमी निवेश को इच्छुक है परंतु पिछड़े जगहों पर निवेश नहीं करते।

PPP में सरकार की वर्तमान नीति

PPP को ज्यादा प्रज्वलित करने हेतु सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। जिसमें सरकार विवादों को निपटारने हेतु त्वरित गति क्रियाविधि का प्रस्ताव पारित करने को लक्ष्यवत है। इसके अलावा निवेश का औद्योगिक अवस्थिति, जन शक्ति प्राप्तिदारी पर विशेष धन दिया जा रहा है।



इस तरह भारत सरकार इस मॉडल में कुछ उपलब्ध कराने, सहायता गारंटी देने तथा विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश को बढ़ावा दे रही है।

निष्कर्ष

PPP मॉडल से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी लाभ पहुँचता है जिससे सरकार के खजाने का महत्वपूर्ण अंश प्राप्त होने से बढ़ता है वह हिस्सा देश की अन्य जरूरतों को पूरा करने में उपयोग होता है। इससे लोगों को रोजगार मिलता है एवं अर्थव्यवस्था नीवेश के विकास में हिस्सा लेते हैं। देश का Fiscal Deficit में भी कमी होती है। और GDP ग्रोथ रेट बढ़ता है।

Excellent!